भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1817

उत्तर देने की तारीख 31 जुलाई, 2023 (सोमवार)

9 श्रावण, 1945 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्वी राज्यों तक परिवहन संपर्क के लिए बजट

1817. डॉ. अमर सिंह:

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों में रेल, वायु और सड़क नेटवर्क तैयार करने के लिए 1,34,200 करोड़ रुपए की लागत से कितनी परियोजनाओं को पूरा करने की योजना है;

(ख) परियोजना-वार बजटीय परिव्यय और व्यय कितना-कितना है; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की पर्यावरणीय संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

*****

(क) संबंधित नोडल मंत्रालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में निम्नलिखित रेल, हवाई और सड़क परियोजनाओं को पूरा करने की योजना हैः-

• रेल कनेक्टिविटी:

81,941 करोड़ रुपये की लागत से 1,909 किमी की कुल लंबाई को कवर करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्ण/आंशिक रूप से पड़ने वाली कुल 19 रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की गई हैं और ये आयोजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इसमें से 482 किमी लंबाई चालू हो चुकी है और इनपर मार्च, 2023 तक 37,713 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

• हवाई कनेक्टिविटी:

नागर विमानन मंत्रालय ने 21.10.2016 को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस)-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है ताकि देश भर में असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और हवाई यात्रा को जनता के लिए किफायती बनाया जा सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उड़ान के तहत रूपसी, तेजू, तेजपुर, पासीघाट, जोरहाट, लीलाबाड़ी, शिलांग, पाकयोंग, ईटानगर और दीमापुर में 64 रूट्स को शामिल करते हुए हवाई अड्डों का संचालन शुरू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2014 में नौ हवाई अड्डे प्रचालन में थे। वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 16 हवाई अड्डे प्रचालनरत हैं। इसके अतिरिक्त, ज़ीरो में एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को भी चालू कर दिया गया है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में 1,543.70 करोड़ रुपये के 13 प्रमुख अवसंरचना कार्य चल रहे हैं।

• सड़क कनेक्टिविटी:

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में 1,02,594 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत वाली 261 सड़क परियोजनाएं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) और राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के माध्यम से कार्यान्वयनाधीन हैं।

इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने तत्कालीन उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएसडीएस) और मौजूदा उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) के अंतर्गत 3,372.58 करोड़ रुपए की 77 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

• इसके अलावा, पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल, हवाई और सड़क कनेक्टिविटी के सुधार के संबंध में एनईसी की स्कीमों के तहत 4,345.16 करोड़ रुपये की 51 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ख) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता की स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को निधियां जारी की हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता की योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई राशि

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**राज्य**	**बजट अनुमान 2022-23**	**2023-24**		
			आवंटन	**अनुमोदित राशि**	**जारी राशि**
1	अरुणाचल प्रदेश	1564.10	1757.00	1254.86	

2	असम	4300.14	3128.00	3128.00	1514.83
3	मणिपुर	467.22	716.00		
4	मेघालय	1049.02	767.00	511.75	
5	मिजोरम	297.50	500.00	399.24	
6	नागालैंड	504.16	569.00	569.00	
7	सिक्किम	551.36	388.00	387.62	258.43
8	त्रिपुरा	349.79	708.00		
	कुल	**9083.29**	**8533**.00	**6250.47**	**1773.26**

(ग) नई परियोजनाएं शुरू करने से पहले आवश्यक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) किया जाता है। मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों द्वारा नियमानुसार अपेक्षित पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरी भी प्राप्त की जाती है।

*****